Allotment of flats to slum Dwellers on cash down basis

489. SHRl SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether slum wings of DDA had invited applications from registered persons for allotment of residential flats on cash down basis under its scheme for Slum Dwellers in November, 1990;

(b) if so, the number of applications received category-wise;

(c) the cost fixed at that time category wise;

(d) whether scrutiny of applications has since been made during the last eight months;

(e) if so, the details thereof alongwith the tentative date for the holding of draw of lots;

(f) if not the reasons therefor; and

(g) whether the delay in holding draw would not increase the cost of flats?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) 1537 applications were received for 92 EWS flats. After scrutiny, 1502 application were found in order. Category-wise break-up of these 1502 applications is as under

Category	No. of applications received
General	1196
Scheduled Castes .	277
Physically Handicapped	4
Ex-servicemen	4
Widows	21

(c) The cost of the flats has been worked out to be Rs. 1,17,0001-.

(d) and (e) Yes, Sir. A draw was held on 30-1-1991 after scrutiny of applications.

(f) and (g) Do not arise in view of reply to parts (d) & (e) above.

Private sector participation in steel sector

490. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to allow private sector participation in the steel sector upto 1 million tonne capacity;

(b) if so, whether Government have since cleared the said proposal; and

(c) if so to what extent the production of steel in the country would be increased?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEB): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Applications from interested parties have been received and are being examined.

मत्स्य उत्पादन

491. डा० निर्मेन्द्र कुमार जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान देश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990–91 के दौरान मछलियों का उत्पादन और निर्यात कितना कितना हुआ ;

(ग) क्या सरकार, समुद्र से मछली पकड़ने के काम में लगे हुए मछुआरों के

लाभ के लिए किसी योजना के लागू करने पर विचार कर रही है ताकि उन्हें आत्म-निर्भर बनाया जा सके और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मूलापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1990-91 के दौरान देश में कुल मत्स्य उत्पादन 38.36 लाख मीटरी टन हुआ और तदनुरूपी अवधि के दौरान निर्यात किया गया समुद्री उत्पाद 1.38 लाख मीटरी टन था ।

(ग) और (घ) समुद्री मछुआरों के लाभ के लिए सरकार द्वारा फिलहाल क्रियान्वयनाधीन तथा 1991-92 वर्ष के लिए क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण उत्पादनोन्मुखी योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण ।

(2) मत्स्य ग्रहण जलयान, जिनकी लम्बाई 20 मीटर से कम हो, द्वारा प्रयुक्त उच्च गति डिजिल तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति ।

(3) नान ट्रालर प्रकार की एफ. आर.पी. मत्स्य ग्रहण नौकाओं, जिनकी लम्बाई 12-15 मीटर हो, को चलाकर अपतटीय पेलैजिक मात्स्यिकी संसाधनों का उपयोग करना ।

(4) डोंगा तथा कैटामारान के बदले में प्लाईवूड मत्स्य ग्रहण नौकाओं को चलाना ।

(5) जलीय प्रदेश में समुद्री मत्स्यग्रहण विनियमन अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पैट्रोल चालित नौका प्राप्त करने के लिए समुद्रवर्ती राज्य सरकारों का वित्तपोषण करना ।

इस्पात और लोहे के मूल्यों में वृद्धि

492. श्री राम जेठमलानी

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये का हाल ही में किए गए अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश में इस्पात और लोहे के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मूल्य-वृद्धि 400 रुपये से 500 रुपये प्रति टन तक हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और ये कदम मूल्य-वृद्धि को रोकने में कहां तक प्रभावी रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा प्रशासित लोहे और इस्पात के मूल्यों में अभी हाल में कोई वृद्धि नहीं की गई । कुछ क्षेत्रों में लोहे और इस्पात की कुछ मदों के खुले बाजार मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु यह पूर्णतया अवमूल्यन के कारण ही नहीं कहा जा सकता ।

देश में इस्पात का उत्पादन

493. श्री राम जेठमलानी

सरदार बूटा सिंह अरोड़ा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल 1991 के फाइनेंशियल एक्सप्रैस में "आउटपुट टू बी 5 लाख टन्स शार्ट आफ टारगेट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;